

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]  
No. 46]

दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936  
DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 275  
[N.C.T.D. No. 275

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2014

फा. सं. 2/70/2003-से-1/अधी.विधी/431-435.—इस सरकार की अधिसूचना सं. फा. 2/70/2003-से-1/अधी.विधी/212-216 दिनांक 14. 2. 2014 के आंशिक संशोधन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रोफेसर (डॉ.) बूषन तिलक कौल को प्रतिनियुक्ति आधार पर दिल्ली न्यायिक अकादमी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

अन्य सभी नियम एवं शर्तें वही रहेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश व उनके नाम पर,  
डा. सौरभ कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त सचिव

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS  
NOTIFICATION**

Delhi, the 28th March, 2014

**No. F. 2/70/2003-S.I/Suptlaw/431-435.**—In partial modification of this Government's notification No.F2/70/2003-S.I/Suptlaw/212-216 dated 14-2-2014, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Prof. (Dr.) Bushan Tilak Kaul as full time Chairperson of the Delhi Judicial Academy on deputation basis.

All other terms and conditions shall remain the same.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy.

**व्यापार एवं कर विभाग**

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2014

**सं.फा. 7(400)/नीति/वैट/2014/1387—1398.**—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उपनियम (2) और (5) (इसके आगे उल्लिखित 'नियमों' के अनुसार) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम (2) के उपनियम (4) के खंड (ख) तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 36 (इसके आगे उल्लिखित 'अधिनियम' के अनुसार) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित बैंकों को किसी भी पंजीकृत व्यापारी या पंजीकृत होने योग्य व्यापारी, डेका देने वाले (टैन धारी) और अनौपचारिक व्यापारी को कर, व्याज, दंड और अन्य कोई राशि जो कि इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय हो, को जमा करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त शासकीय को कोषागार के रूप में घोषित करता हूँ:

1. इलाहाबाद बैंक 2. एकसैस बैंक 3. बैंक ऑफ बड़ौदा 4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5. केनरा बैंक 6. सैट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
7. कॉर्पोरेशन बैंक 8. एचडीएफसी बैंक 9. आईसीआईसीआई बैंक 10. आईडीबीआई बैंक 11. इण्डियन बैंक 12. इण्डियन ऑवरसीस बैंक 13. कोटक महिन्द्रा बैंक 14. ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस 15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 16. पंजाब नेशनल बैंक 17. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 18. सिंडिकेट बैंक 19. यूको बैंक 20. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 21. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया 22. विजया बैंक ।
2. उक्त प्राधिकृत वर्णित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन हैं:—
- (i) नीचे दिये गये खण्ड (ii) के संदर्भ में, जगा राशि को केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम (इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा) ही भुगतान किया जायेगा ।
- (ii) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की राभी शाखाएं और पंजाब एण्ड सिंध बैंक की व्यापार भवन शाखा में, ऑन लाइन भुगतान के अतिरिक्त, भौतिक रूप से भी ऑफ लाइन भुगतान प्राप्त करेंगी (भुगतान नकद/चैक के द्वारा विभाग की वेबसाइट से प्रकाशित चालान द्वारा), जैसा कि वर्णित प्रक्रिया के प्रवाह में बताया गया है। अगर किसी भी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा को बैंक ने ऑफ लाइन भुगतान की स्वीकृति नहीं दी गई तो बैंक इसकी सूचना विभाग में देगा । किसी भी अधिकृत शाखा द्वारा भुगतान की प्राप्ति को भना करना, इस प्राधिकरण की त्रुटि गाना जायेगा ।
- (iii) बैंक के सॉफ्टवेयर को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑन लाइन/ऑफ लाइन भुगतान करने की प्रक्रिया के अनुरूप, जैसा कि प्रक्रिया के प्रवाह में दर्शाया गया है, को विकसित किया जायेगा ।
- (iv) चालान के ऑन लाइन/ऑफ लाइन भुगतान की प्रक्रिया को विभाग की वेबसाइट से आरंभ किया जायेगा । विभाग की वेबसाइट से प्रकाशित चालान एक अद्वितीय पहचान पत्र नम्बर दर्शायेगा ।
- (v) किसी भी स्थिति में बैंकों द्वारा कोई भी भुगतान हाथ से लिखे गये चालान द्वारा या सीधे तौर पर उनके पॉस्टल द्वारा, स्वीकार नहीं किया जायेगा । जबकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक की व्यापार भवन शाखा को, अपंजीकृत व्यापारियों तथा अनौपचारिक व्यापारियों के द्वारा जमा करने के लिए हाथ से लिखे गये चालान स्वीकृत होंगे ।
- (vi) एकत्र की गई राशि को भारतीय रिजर्व बैंक, पर्लियार्मेंट रट्रीट, नई दिल्ली में भुगतान की वसूली के अगले कार्य दिवस तक जगा की जायेगी ।
- (vii) प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक किए गए भुगतान को उसी दिन के भुगतान में गिना जायेगा और रात्रि आठ बजे से अगले दिवस प्रातः 8 बजे के बीच किए गए भुगतान को अगले कार्य दिवस के भुगतान में गिना जायेगा । रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में किसी भी समय किए गए भुगतान को अगले कार्य दिवस के भुगतान में गिना जायेगा ।
- (viii) विलम्ब से प्रेषित की जाने वाली राशि पर व्याज लगाया जायेगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अद्यतन व्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक होगा ।
- (ix) बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे ।

(x) ऑन लाइन भुगतान व्यापारी/ठेकेदार (टैन धारी) या किसी भी व्यक्ति के जमा खाता/चालू खाता से किया जा सकता है।

3. बैंक द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चालान पहचान पत्र नम्बर, सफलतापूर्वक भुगतान करने की प्राप्ति को व्यापारी द्वारा जमा करने का सबूत माना जायेगा। व्यापारी अद्वितीय चालान पहचान पत्र नम्बर को अपनी विवरणी/विवरणी सत्यापन फार्म में, नियम 28 के उपनियम (3क) तथा नियम 59 के उपनियम (2) के उद्देश्य, हेतु वर्णित करेगा।

4. सभी बैंक व्यापारी विवरण के अनुसार, विभाग की वेबसाइट से निकाली गई चालान तथा भारतीय रिजर्व बैंक को जमा राशि की सत्यापित फाइल को अपलोड करेंगे। सत्यापित फाइल को इलेक्ट्रोनिकली विभाग की वेबसाइट पर उसी दिन अपलोड करना होगा जिस दिन को बैंक में वह भुगतान हुआ है।

5. कोई भी चालान/स्कोल का गौतिक व्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं भेजा जायेगा। केवल स्कोल का संक्षिप्त विवरण जो कि पिछले दिन का जमा विवरण होगा, सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित प्रारूप में, भेजेंगे।

दिनांक:

क्रम सं.	अधिनियम	चलानों की संख्या	राशि (रुपये)
1	2	3	4

दिनांक:

पिछले दिन से आगे (रुपये)	दिन के 2000 धंडे तक एकत्रित (रुपये)	भारतीय रिजर्व बैंक को आज जमा की गई राशि (रुपये)	राशि जो अभी जमा करनी है (रुपये) (1)+(2)–(3)
1*	2	3	4

\* कॉलम 1= पिछले दिन का कॉलम 4

6. बैंक के सॉफ्टवेयर को विभाग द्वारा आपेक्षित राशी प्रकार के एग.आई.एस. प्रतिवेदन उत्पन्न करने होंगे और इलेक्ट्रोनिक डाटा को, DD/MM/YYYY और HH:MM:SS AM/PM प्रारूप में, संचारित/दैनिक आधार पर विभाग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड करना है।

7. अधिकृत बैंक की नोडल शाखा सभी गामलों जो कि जमा राशि के भुगतान से संबंधित है, इस विभाग से समन्वय करेगी तथा संबंधित व्यक्ति का नाम/भौवाइल नं./ई-मेल इस कार्यालय को भेजेगी।

8. यह अधिसूचना इस विषय पर पिछली सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, 01 अप्रैल, 2014 से लागू होगी।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

**DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES  
NOTIFICATION**

Delhi the 28th March, 2014

**No. F. 7(400)/Policy/VAT/2014/1387-1398.**—In exercise of the powers conferred under sub-rule (2) and (5) of Rule 31 of Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as 'the Rules') read with clause (b) of sub-rule (4) of Rule 2 of the Rules and Section 36 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as 'the Act'), I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, do hereby notify the following banks located in the National Capital Territory of Delhi as the 'Appropriate Government Treasury' for collection of tax, interest, penalty or any other amount due under the Act or Central Sales Tax Act, 1956 from the dealers registered or liable to be registered under the Act, casual traders and contractees (TAN holders):

1. Allahabad Bank 2. Axis Bank 3. Bank of Baroda 4. Bank of Maharashtra 5. Canara Bank 6. Central Bank of India 7. Corporation Bank 8. HDFC Bank 9. ICICI Bank 10. IDBI Bank 11. Indian Bank 12. Indian Overseas Bank 13. Kotak Mahindra Bank 14. Oriental Bank of Commerce 15. Punjab & Sind Bank 16. Punjab National Bank 17. State Bank of India 18. Syndicate Bank 19. UCO Bank 20. Union Bank of India 21. United Bank of India 22. Vijaya Bank.

2. The Authorisation of above said banks, in addition to the RBI's regulations, shall be subject to the following conditions:

- Subject to clause (ii) below, the amount shall be collected in e-payment mode (i.e. via internet banking) only.
- All branches of State Bank of India and Vyapar Bhawan Branch of Punjab & Sind Bank, would also accept physical offline payment (payment through cash/ cheque after printing the challan from the Department's website), in addition to e-payment, as per the prescribed process flow. The State Bank of India would specifically inform the Department in case any of its branch in NCT of Delhi is not allowed to collect physical offline payments. Refusal to accept payment by an allowed Branch would be considered as a breach of this authorisation.
- The Bank's software shall be developed in accordance with process flow for online/offline payment available on department's website.

(iv) The process of filling up of challan for online as well as offline payment shall have to be initiated from the departmental web-site. The challan printed from the department's website would carry a unique ID.

(v) No payment would be accepted by banks against hand written challan or directly through their portal in any case. However, Vyapar Bhawan Branch of Punjab & Sind Bank would be allowed to accept payments against handwritten challan from unregistered dealers and casual traders only.

(vi) The amount collected shall be remitted to Reserve Bank of India, Parliament Street, New Delhi latest by the next working day of the realisation of the payment by the Bank.

(vii) Payments made between 8.00 A.M to 8.00 P.M on any working day will be accounted for on the same day and those after 8.00 P.M till before 8.00 A.M on next day will be accounted in the next working day's payment. Further, payments made at any time on Sundays and holidays will be accounted in the next working day's payment.

(viii) The interest on delayed remittance to RBI shall be levied at the bank rate plus 2% or as notified by RBI from time to time.

(ix) The banks shall adhere to security and other provisions of the Information Technology Act, 2000.

(x) The online payment can be made from saving/current account of dealer/contractee or any other person on their behalf.

3. The challan having unique challan identification number (CIN) generated by the Bank after having received the payment successfully from a dealer, shall be the only acceptable proof of payment by that dealer. The CIN would need to be disclosed by the dealer with the return/return verification form for the purpose of sub-rule (3A) of Rule 28 and sub-rule (2) of Rule 59 of the Rules.

4. Banks shall upload the file containing dealer-wise reconciliation between the challans downloaded from the Department's website and the payment remitted to RBI by Banks. The reconciliation file shall be uploaded electronically on the website of the department on the next day of realisation of payment by the Bank.

5. No physical statement of scroll / challans would be sent to RBI. Only summary of scroll shall be sent by the banks to RBI at the time of making payment of the previous day's collection in the following formats:

Date:

Sr No.	Act	No. of Challans	Amount (Rs.)
1	2	3	4

Date:

Carry Forward from previous Day (in ₹)	Collection as on day till 2000 Hrs (in ₹)	Remitted to RBI today (in ₹)	Realised amount yet to be remitted (in ₹)
1*	2	3	(1)+(2)-(3)
			4

\* Col.1= Col.4 of the previous day

6. All MIS reports, as required by the Department, shall be electronically uploaded on the website of the Department every day, indicating specifically the time of successful payment in DD/MM/YYYY and HH:MM:SS AM/PM format.

7. The Nodal branch of the authorised bank shall coordinate all matters relating to payment with the department and the name/ mobile/ email of the contact person shall be communicated to our office.

8. This notification supersedes all previous notifications on the subject and shall come into force with effect from 1st April, 2014.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, VAT